सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

P19/II/DRSSA-51/MP/2019-20

23 /07/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers/Banks.

Sir,

Sub: 1.Payment of DR on pension at the revised rate of 148 percent to the retired Officers of Madhya Pradesh State Judicial Services w.e.f. 01/07/2018 –reg.
2.30 percent Interim relief payable on basic pay to the Judicial Officers as per the recommendations of the Second National Pay Commission –reg.

Ref: 1.SSA No. Pension/935, dated:03/06/2019 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh.
2.Lr.No.F.No.3(a)19/2003/21-B(I)4552 dated 04/10/2018 from the Law & Legislative Department, Government of Madhya Pradesh.
3.Lr.No.F.No.2212/2018/21-B(I) dated: 18/05/2018 from the Law & Legislative Department, Government of Madhya Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh regarding payment of Dearness Relief on pension at the revised rate of 148 percent to the retired Officers of Madhya Pradesh State Judicial Services w.e.f. 01/07/2018 and 30 percent Interim relief payable to the Judicial Officers as per the recommendations of the Second National Pay Commission . The same is being placed in the official website of this office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

23/7/19

Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

DR 1488 Judicial

P19

No. Pension/ 935 Date :- 3-6-19

Under Special Seal Authority

P19/II/DRSSA/51
27/6/19

10627
24.6.19

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Aurnachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27. Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E) Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G Road, Thrivanathapuram	695039
13.	Office of the Principal Accountant General (A&E), Tharkhand, Ranchi	834002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Cicil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Unior Territory of Chandigarh, Sector 17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102

24.	Accountant General (A&E), Tamil Nanu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27.	Accountant General (A&E), Uttrakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2 Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (v), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

विषयः– 1. म.प्र. न्यायिक सेवा के से.नि. अधिकारियो को दिनांक 01.07.2018 से 148 प्रतिशत पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान बाबत्।

2. द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग की अनुशंसानुसार न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर देय 30 प्रतिशत राहत बाबत्।

संदर्भः– 1. म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक फा.क्र.3(ए) 19/2003/21–ब(एक)4552 दिनांक 04.10.2018

2. म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक फा.क्र.2212/2018/21–ब(एक) दिनांक 18.05.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2018 से देय मंहगाई राहत 148 प्रतिशत एवं दिनांक 01.01.2016 से देय 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के भुगतान के आदेशों की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेशों की प्रतियां आपके अधीन समस्त कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने की व्यवस्था करें।

तदनुसार उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

लेखा अधिकारी/पेंशन

English Latter

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21–ब(एक)4552 भोपाल, दिनांक 3.10.2018

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2018 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।**

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 11.09.2018 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2018 से 142 से बढ़ाकर 148 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत सदस्यों को दिनांक 01.07.2018 से पेंशन पर राहत 142 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 11.09.2018 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2018 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. फा.क्र.3(ए) 19/2003/21–ब(एक)/4552 भोपाल, दिनांक3.10.2018

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल,
21. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
22. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
23. समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
24. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
25. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
30. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
32. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
33. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
34. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
36. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

37. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
38. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
39. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
40. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
41. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल,
42. महालेखाकार, अन्य राज्य.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

03/10/2018

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 05.05.2018
18.5.18

फा.क्र. 2212/2018/21-ब(एक), राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27 मार्च 2018 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिनांक 09.03.2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ (वेतन) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुए निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फेमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान करता है :-

1. समस्त केटेगरी/रेंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान जाती है।

2. वेतन में की गई उक्त बढ़ोत्तरी पृथक वेतन के रूप में मानी जाएगी एवं इस पर कोई डी.ए. (महंगाई भत्ता) देय नहीं होगा।

3. उक्त अंतरिम राहत के बकाया (एरियर) की गणना दिनांक 01.01.2016 से की जावेगी।

4. उक्त अंतरिम राहत पेंशनर एवं परिवार पेंशनर्स को भी समान रूप से दिनांक 01.01.2016 से देय होगी एवं उसी अनुरूप बकाया (एरियर) भी देय होगा।

5. उक्त अंतरिम राहत के देय बकाया (एरियर) का पूर्ण भुगतान 30 जून, 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जावेगा।

6. उपरोक्त प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जावेगा।

यह अधिसूचना म.प्र. शासन, वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. क्रं. 931/18/वित्त/नियम/चार.... दिनांक 16-5-18... के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर.के. वाणी) 18.5.18
प्रभारी प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

श्री .... विभाग के .... वित्त विभाग के .... दिनांक 16-5-18 द्वारा पृष्ठांकित 931/18/वित्त/नियम/चार

निरंतर....2

Office of the Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh

No. Pension/935 Dated 03.06.2019

To

12.	The Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M G Road, Thiruvananthapuram	695039

Sub :- 1. Payment of relief on pension at the revised rate of 148 percent to the retired Officers of M. P. Judicial Services, w.e.f. 01.07.2018- reg.
2. 30 percent relief payable on basic pay to the Judicial Officers as per the recommendations of the Second National Pay Commission - reg.

Ref :- 1. Order No. F No. 3(A)19/2003/21-B (I) 4552 dated 04.10.2018 of the Law & Legislative Affairs Department, Government of M.P.
2. Order No. F No. 2212/2018/21-B (I) dated 18.05.2018 of the Law & Legislative Affairs Department, Government of M.P.

Sir,

Through the above referred letter, copy of the orders for payment of dearness relief at the rate of 148 percent payable from 01.07.2018 and 30 percent interim relief payable from 01.01.2016 to the retired officers of M. P. Judicial Services has been received in this office. Kindly make arrangement for sending the copies of the above orders to all the Treasury Officers under your jurisdiction, for necessary action.

Accordingly, copy of the above orders is forwarded for appropriate action.

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/Pension

Government of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Department

F. No. 3(a)19/2003/21-B(I)4552 **Bhopal, dated 03.10.2018**

To

The Registrar General
M P High Court
Jabalpur (M P)

Sub :- Payment of relief on pension at revised rate to the retired officers of the Madhya Pradesh Judicial Services, w.e.f. 01.07.2018

Through Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi, Memo no. 1/3/2008-E-II(B), dated 11.09.2018, sanction has been accorded for the payment of dearness allowance at the rate of 148 percent increased from 142 percent w.e.f. 01.07.2018 to those serving employees of central government receiving pre revised Sixth Pay Scale.

Under Rule-9 of Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension & Other Retirement Benefits) Rules, 2010, sanction of dearness allowance is accorded to the serving members of Judicial Services also in accordance with the dearness allowance granted to Central employees by the Central Government, from time to time. Under Rule-11(3) of the above Rules, 2010, the same revised rates of dearness allowance/relief to the serving members shall be applicable to the members retired from Judicial Services.

Hence, sanction is accorded by the State Government for the payment of relief on pension at the rate of 148 percent increased from 142 percent, w.e.f. 01.07.2018 to the retired members of the Madhya Pradesh Judicial Services, under Rule-11(3) of Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension & Other Retirement Benefits) Rules, 2010.

(1) Regularization of dearness relief at revised rates shall be done as per the method given in Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi, Memo No. 1/3/2008-E-II(B), dated 11.09.2018.
(2) Payment of dearness relief under these orders shall be made in cash w.e.f. 01.07.2018.
(3) In case of finding excess payment contrary to this order, the amount of excess payment shall be recoverable from the officer receiving the concerned payment.

In the name and by orders of the
Governor of Madhya Pradesh
/
(Satyendra Kumar Singh)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh,
Law & Legislative Affairs Department

Endt F No. 3(a)19/2003/21-B(I)/4552 **Bhopal, dated 04.10.2018**

Copy to :-

41. Under Secretary, Monitoring (for uploading in Departmental Website) Law Department, Bhopal

Sd/-
(Ratnesh Chandra Singh Bisen)
Secretary
Government of Madhya Pradesh
Law & Legislative Affairs Department

Government of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Department

NOTIFICATION

Bhopal, dated 05.05.2018
18.05.2018

F No. 2212/2018/21-B(I), Accepting the report/recommendations regarding interim relief (Pay) to the Judicial Officers, submitted on 09.03.2018 by the Second National Judicial Pay Commission constituted under the chairmanship of the Honourable Justice Shri P Venkatarama Reddy, under the directions given in order dated 27th March, 2018 of the Honourable Supreme Court, interim relief is granted by the State Government, to the Judicial Officers, Pensioners and Family Pensioners of Madhya Pradesh State, as per the following points.

1. Interim relief of 30 percent on basic pay is granted to the judicial officers of all category/rank.

2. The above increase in pay shall be considered as separate pay and no DA (Dearness Allowance) shall be payable on it.

3. The calculation of arrear of above dearness relief shall be done from 01.01.2016.

4. The above interim relief shall be equally payable to the pensioners and family pensioners also from 01.01.2016 and arrear shall also be payable accordingly.

5. The complete payment of arrear of above interim relief shall be ensured by or before 30th June, 2018.

6. The amount granted under interim relief as above shall be treated as adjustable in future under the final report/recommendations of the Reddy Pay Commission.

This notification is issued in continuation to the consent of the Finance Department, Government of M.P., in U. O. No. 931/18/Finance/Rules/IV dated 16.05.18.

In the name and by orders of
the Governor of Madhya Pradesh
Sd/-
(R K Vani)
Principal Secretary In-charge
Government of Madhya Pradesh
Law & Legislative Affairs Department

190
91-19
P-19